

ट्रंप की ‘‘ग्रीनलैंड’’ पर आधिपत्य जमाने की धमकी से यूरोप में खलबली

वैनेज़ुएला पर सैनिक कार्यवाही के बाद, विश्व ट्रंप की ग्रीनलैंड की धमकी को केवल बड़बोलापन नहीं मान रहा। बल्कि, ट्रंप के गैर जिम्मेवारानापन व ‘‘अनप्रेडिक्टिव सोच’’ की निशानी मान रहा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के इस बयान पर, कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य बल ‘‘हमेशा एक विकल्प’’ है, डेनमार्क ने कड़ी राजनयिक प्रतिक्रिया दी है और नाटो में चिंता की लहर दौड़ गई है। हालांकि वॉशिंगटन का कहना है कि वह सिर्फ सभी विकल्प खुले रख रहा है। ये टिप्पणियाँ आर्कटिक द्वीप को अमेरिका के नियंत्रण में लाने की ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही इच्छा की अब तक की सबसे आक्रामक अभिव्यक्ति हैं। यह बयान वैनेज़ुएला में लाने की ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही इच्छा की अब तक की सबसे आक्रामक अभिव्यक्ति हैं। यह बयान वैनेज़ुएला में हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान

- ग्रीनलैंड, डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा रहा है और डेनमार्क, नाटो का शुरु से सदस्य है. अब ‘‘ग्रीनलैंड’’ पर सैनिक कार्यवाही करना, नाटो के सदस्य के खिलाफ सैनिक आक्रमण है और नाटो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूरोप में अमेरिका की मदद से खड़ा किया गया संगठन है, जिसने यूरोप में शांति और सुरक्षा बनाए रखी, रूस की तथाकथित आक्रामक सोच की छाया में।
- नाटो के अन्य सदस्यों, जैसे टर्की व स्कैंडिनेवियन देशों ने अमेरिका की धमकी के खिलाफ आवाज़ उठाई है।
- इन देशों व अन्य यूरोपीय देशों का तर्क है, अमेरिका का हित नाटो सदस्यों में आपसी सहयोग बढ़ाने में है, न कि उन्हें आपस में लड़ा कर नाटो का विघटन करने में।

के बाद आया है, जिससे सहयोगी देशों में अमेरिका की अतिश्रुतिता को लेकर चिंता और बढ़ गई है।

वाइट हाउस ने ग्रीनलैंड को एक रणनीतिक संपत्ति बताया है, जिसकी अहमियत रूस और चीन के साथ

आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण और बढ़ गई है। अधिकारियों का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है और कहा गया है कि लाखों लोग भारी प्रदूषण का शिकार हैं।

(फंक्शनलिटो असेसमेंट रिपोर्ट) के अनुसार, मध्य प्रदेश में पानी के केवल 63.3 प्रतिशत नमूने गुणवत्ता परीक्षणों में पास हुए, जबकि राष्ट्रीय औसत 76 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘मध्य प्रदेश के गाँवों में एक तिहाई पेयजल पीने योग्य नहीं है’

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 जनवरी। मध्य प्रदेश के गाँवों में, पेयजल चुपचाप सार्वजनिक स्वास्थ्य का हथियार बन गया है। केन्द्रीय सरकार के जल जीवन मिशन द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एक तिहाई से अधिक पेयजल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, जिससे लाखों लोग अदृश्य, लेकिन जानलेवा प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं।

4 जनवरी 2026 को जारी की गई कार्यक्षमता आकलन रिपोर्ट

‘चीन, रूस, क्यूबा और ईरान को बाहर निकालो’

ट्रंप ने वैनेज़ुएला की नई अंतरिम सरकार के लिए निर्देश जारी किए

- ट्रंप ने नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगज़ से कहा कि चीन, रूस, ईरान व क्यूबा से कोई आर्थिक संबंध नहीं रखें।
- ट्रंप ने यह भी कहा कि तेल उत्पादन में सिर्फ अमेरिका के साथ भागीदारी की जाए और ‘‘हैंवी कूड’’ सिर्फ अमेरिका को बेचा जाए।
- ट्रंप के इन दो दूक आदेशों से यह स्पष्ट है कि वैनेज़ुएला का प्रशासन एक तरह से वे ही चला रहे हैं।

बाद, डेल्सी रॉड्रिगज़ ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है, जबकि ट्रंप का कहना है कि वे अब इस दक्षिण अमेरिकी देश को नियंत्रित कर रहे हैं।

अब, एबीसी ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप प्रशासन ने वैनेज़ुएला के नए नेतृत्व से कहा है कि उन्हें अपने तेल भंडार से अधिक तेल निकालने की अनुमति तभी दी जायेगी, जब वे उनकी शर्तों का पालन करेंगे।

सूत्रों ने कहा, ‘‘सबसे पहले तो,

वैनेज़ुएला को चीन, रूस, ईरान और क्यूबा से सम्बंध खत्म करने होंगे और आर्थिक संबंधों को तोड़ना होगा। दूसरे, वैनेज़ुएला को केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तेल उत्पादन में साझेदारी करने पर सहमत होना होगा और हैंवी कूड बेचते समय अमेरिका को प्राथमिकता देनी होगी।’’ ज्ञातव्य है कि चीन लंबे समय से वैनेज़ुएला का करीबी साथी है और यह वैनेज़ुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार है।

‘ऑपरेशन वैनेज़ुएला बहुत साफ-सुथरी व सर्जिकल सैनिक कार्यवाही थी’

पर, अब मालूम पड़ रहा है कि अमेरिका का यह दावा काफी थोथा व असत्य था, क्योंकि अब सब स्वीकार कर रहे हैं कि कम से कम 80 लोग मारे गए थे, कई सारे घर व मकान तहस-नहस हो गए थे, अमेरिकी बमबारी में

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 जनवरी। काराकस, वैनेज़ुएला में एक साफ़-सुथरा और सर्जिकल ऑपरेशन करने के अमेरिकी दावों के विपरीत, अब यह साफ हो गया है कि देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण की पूरी कार्रवाई बेहद हिंसक और खून-खराबे वाली थी। कम से कम 80 लोग मारे गए हैं। इनमें ड्यूटी पर तैनात वैनेज़ुएला और अन्य विदेशी भाड़े के सैनिकों के साथ-साथ वे आम नागरिक भी शामिल हैं, जो गोलीबारी की चपेट में आ गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि सैन्य हमलों में उनके घर तबाह हो गए। वैनेज़ुएला के अधिकारियों को आशंका है कि मरने वालों की अंतिम संख्या इससे कहीं

- जैसा कि अब अमेरिका ने भी स्वीकार किया है कि 150 अमेरिकी हवाई जहाजों ने आक्रमण में भाग लिया था, समुद्र के जहाजों, अन्य ट्रकों व ट्रैकों के अलावा। सभी को विशेषकर वैनेज़ुएला को आभास था कि अमेरिका आक्रमण करने वाला है तथा वैनेज़ुएला की आर्मी व वायु सेना तैयार थी लड़ाई के लिए। अतः आसमान में ‘‘डॉंग फाइटर्स’’ हुई व जमीन पर काफी गोलाबारी भी देखी गई थी।
- अमेरिका ने अब ‘‘डिमांड’’ रखी है. वैनेज़ुएला के समक्ष कि वह 50 मिलियन ऑयल दे, अमेरिका को, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचने के लिए तथा आमदनी अमेरिका के कोष में जमा होगी तथा थोड़ा बहुत अंश वैनेज़ुएला को भी मिलेगा।

अधिक हो सकती है।

डॉनल्ड ट्रंप ने पूरे अभियान को

बेहद हिंसक, लेकिन प्रभावी बताया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने एसआई भर्ती मामले में हाई कोर्ट में बहस पूरी की।

हो तो उसके चलते पूरे चयन तंत्र को दूषित मानकर भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश राज्य सरकार व अन्य की अपील पर दिए।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वंशिका यादव के मामले में तय किया है कि जब तक किसी भर्ती में व्यापक और संगठित स्तर पर सिस्टमैटिक गड़बड़ी सिद्ध न हो तो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 7 जनवरी। वैनेज़ुएला पर डॉनल्ड ट्रंप की कार्यवाही और टिप्पणी की वजह से उन देशों ने एक एंटी अमेरिकन मोर्चा बना लिया है, जो अब तक बिखरे हुए थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत ही चतुर और परोक्ष बयान वह है, जो प्रमुख यूरोपीय देशों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड को ताकत से कब्जा करने की धमकी के खिलाफ दिया है। ग्रीनलैंड पर ताकत से कब्जा करना अब एक वास्तविक खतरा बन गया है, विशेष रूप से वैनेज़ुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करने के बाद। इस कार्रवाई की दुनिया भर में, मित्र देशों और शत्रु देशों, दोनों द्वारा कड़ी निंदा की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक तनाव को और बढ़ाते हुए, डॉनल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी जानबूझकर ग्रीनलैंड पर अपना दावा दोहराकर अमेरिका के दखल देने की प्रवृत्ति के खतरे को बढ़ा रहे हैं। इससे अमेरिका के नाटो सहयोगी गुस्से में हैं और सभी हैरान हैं।

- इस मुद्दे पर ऐसे-ऐसे देश भी एक मंच पर नज़र आए जो आपस में काफी कटुता पाले हुए हैं।
- सब का एक ही मत है कि ग्रीनलैंड के बाशिंदों को ही अन्ततोगत्वा अधिकार प्राप्त हैं कि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं या किसी देश का आधिपत्य स्वीकार करना चाहते हैं।
- ग्रीनलैंड के निवासियों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपना निर्णय सुनाया है कि वे स्वाधीन रहना चाहते हैं, किसी अन्य देश में शामिल होकर अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहते। अतः इन लोगों पर इस मुद्दे पर जोर-जबरदस्ती व दबाव डालना गैर-कानूनी व गैर वाजिब है।

यूरोपीय देशों ने स्पष्ट रूप से अपनी अस्वीकृति और निराशा व्यक्त की है, अमेरिका द्वारा देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक व्यवहार के सभी मानदंडों को खलकर निंदा भी की जा रही है। ग्रीनलैंड यूरोपीय महाद्वीप और अमेरिकी महाद्वीप के बीच स्थित है।

यूरोप ने विशेष रूप से कहा है कि ग्रीनलैंड वहाँ की जनता का है और किसी और देश का नहीं है और उसकी

सहयोगी की पत्नी ने ग्रीनलैंड का एक नक्शा प्रकाशित किया था, जिसमें पूरे ग्रीनलैंड क्षेत्र पर अमेरिकी ध्वज लहराते हुए दिखाया गया था।

कुछ यूरोपीय देशों का कहना है कि डॉनल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड के बारे में बयान ‘‘बेहद मुख्तयापूर्ण’’ था।

डॉनल्ड ट्रंप ने बार-बार कहा है कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात की ज़रा भी परवा नहीं की, वहां के लोगों ने स्पष्ट रूप से इस योजना का विरोध किया है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड को आत्मनिर्णय का अधिकार है, जैसे किसी अन्य देश को होता है।

वैनेज़ुएला पर अमेरिकी आक्रमण और राष्ट्रपति के अपहरण ने दुनिया भर में एंटी-अमेरिका मोर्चे को फिर से सक्रिय कर दिया है। इस कदम ने दुनिया के विभिन्न देशों को अमेरिका के खिलाफ कर दिया है और विभिन्न नेताओं ने इसके पड़ोसी देशों में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है।

तुर्कों के राष्ट्रपति, रेसेप तईप एर्दोग़ान, ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संसद का सत्र 28 से संभव

नई दिल्ली, 07 जनवरी। केंद्र सरकार एक फरवरी को आम बजट पेश कर सकती है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की बुधवार की हुई बैठक में संसद के आगामी बजट सत्र की तारीखों का प्रस्ताव रखा गया।

राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने संसद के बजट

- एक फरवरी को केन्द्रीय बजट पेश होगा।

सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से करने और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार, इन तारीखों पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित किया जाता है। पहले और दूसरे हिस्से के बीच अवकाश रखा जाता है, ताकि संसदीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें।

झारखंड में जंगली हाथी ने 7 को मारा

चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम), 07 जनवरी। नोवामुंडी प्रखंड के जेटेया थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबरिया गांव में 6 जनवरी की रात जंगली हाथी के हमले से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे परिवार के एक सदस्य की भी हाथी

- एक परिवार घर पर सो रहा था, जब हाथी ने अचानक हमला किया।

के हमले में जान चली गई। घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। बताया गया कि सभी लोग अपने घर में सो रहे थे, तभी हाथी ने अचानक घर पर हमला कर दिया। इस दौरान परिवार का एक बच्चा किसी तरह जान बचाने में सफल रहा। बाबरिया गांव में मृतकों की पहचान सनातन मेराल, उनकी पत्नी जॉकी कुई, उनके दो मासूम बच्चों और मोगदा लागुरी (दूसरे परिवार से) के रूप में हुई है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)